PK टाइम्स

दैनिक लोक टुडे

RNI No. RAJHIN/2013/50649

जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

www.loktodaynews.com

pktimesnews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk–timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 278 | शनिवार 25 अप्रैल, 2026 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4

फिर बम से उड़ाने की धमकी...

ईमेल की जांच और परिसरों की तलाशी, आरोपियों का नहीं सुराग, इंटेलिजेंस फेलियर

हर छोटे दफ्तर से लेकर विधानसभा तक बार-बार मिल रही है धमकियां, कौन देता आज तक पता नहीं ?

● लोक टुडे

जयपुर। राजस्थान विधानसभा को शुक्रवार को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 12 दिनों में यह दूसरा मौका है जब विधानसभा को इस तरह निशाना बनाने की कोशिश की गई है। विधानसभा सचिवालय को सुबह करीब सवा 8 बजे ईमेल प्राप्त हुआ। इसमें चेतावनी दी गई थी कि दोपहर ठीक 1 बजे आत्मघाती हमला किया जाएगा। ईमेल में दावा किया गया कि दो हमलावर राजीव गांधी की हत्या की तरह बेल्ट बम पहनकर धमाका करेंगे। सूचना मिलते ही परिसर को तुरंत खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता (BDS), डॉग स्क्वॉड और सिविल डिफेंस की टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। गहन तलाशी के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और पुलिस ने इसे एक हॉक्स कॉल (झूठी धमकी) करार दिया है।

इन्हें पकड़ना मुश्किल क्यों है?

अपराधी अपनी लोकेशन छिपाने के लिए VPN (Virtual Private Network) और प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, कई बार ये ईमेल उन देशों के सर्वर से भेजे जाते हैं जहाँ से जानकारी जुटाने में अंतरराष्ट्रीय कानूनी अड़चनें आती हैं।

खुफिया विभाग और सुरक्षा पर उठते सवाल

बार-बार मिल रही धमकियों के बावजूद अब तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 13 अप्रैल 2026 को भी विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। केवल राजस्थान ही नहीं, हाल के महीनों में दिल्ली विधानसभा और बिहार विधानसभा को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां और साइबर सेल अब ईमेल के आईपी एड्रेस और मूल स्थान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आरोपियों को पकड सके।

हर दिन चेकिंग की मांग

विधानसभा की ओर से पत्र लिखकर एएस चेकिंग की मांग की गई है। इस नीति के प्रावधान है कि नियमित डेली रूटीन पर डॉग स्क्वायड और सुरक्षा एजेंसी की ओर से परिसर की चेकिंग की जाती है।

जांच एजेंसियो के लिए चुनौती

पिछले कुछ समय से छोटे दफ्तरों, स्कूलों से लेकर विधानसभाओं तक बम की धमकियों (Bomb Threats) का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। जांच एजेंसियों के लिए चुनौती यह है कि ये धमकियाँ अक्सर डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके दी जा रही हैं, जिससे दोषियों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि, हाल की गिरफ्तारियों से कुछ अहम खुलासे हुए हैं। मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस ने मैसूरु (कर्नाटक) से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया, जिसने देश भर के उच्च न्यायालयों, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में 1,000 से अधिक फर्जी ईमेल भेजे थे। वह अदालती मामलों में न्याय न मिलने से नाराज था और अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN और अंतरराष्ट्रीय सर्वरों का इस्तेमाल कर रहा था। मार्च 2026 में ही पश्चिम बंगाल से सौरव विश्वास नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया, जो 'e&petseller.com' जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए हैक किए गए ईमेल अकाउंट बेचता था।

इन अकाउंट्स का इस्तेमाल धमकियाँ देने के लिए किया जा रहा था। कई धमकियों के पीछे खालिस्तान नेशनल आर्मी जैसे नामों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ ईमेल के तार हंगरी (बुडापेस्ट) और रूसी ईमेल सर्विस (mail.ru) से भी जुड़े पाए गए हैं। कुछ मामलों में छोटे स्तर पर शरारती तत्व या यहाँ तक कि स्कूली छात्र भी परीक्षा टालने जैसे निजी कारणों से ऐसी धमकियाँ देते पकड़े गए हैं।

आग से दहला विद्युत भवन का रिकॉर्ड रूम

जरूरी दस्तावेजों के जलने की आशंका, अलार्म बजते ही मची अफरा-तफरी

जयपुर। आज जयपुर में सहकार मार्ग पर स्थित विद्युत विनियामक भवन की चौथी मंज़िल पर आग लग गई। धुआं उठना शुरू होते ही कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई, जिसके चलते कर्मचारियों को बिल्डिंग खाली करनी पड़ी। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चौथी मंजिल पर जिस कमरे में आग लगी थी, वह असल में एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, जिसे फिलहाल रिकॉर्ड रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसमें जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी। प्रमुख ऊर्जा सचिव आरती डोगरा और बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे।

कुर्सियों को भी आग से नुकसान पहुंचा

बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन राजेश शर्मा ने कहा- यह कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहां कुछ जरूरी रिकॉर्ड रखे थे। हालांकि, रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। इन रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़्ड रूप में भी सुरक्षित रखा गया है। फिर भी, कॉन्फ्रेंस हॉल की हालत का जायज़ा लेने पर पता चला कि कुछ दस्तावेज़ जल गए थे, और कुर्सियों को भी आग से नुकसान पहुंचा है। इसके बाद रिकॉर्ड्स को दूसरी जगह शिफ़्ट कर दिया गया है। हमारे यहां एक अलार्म सिस्टम लगा है। जैसे ही अलार्म बजा, संबंधित अधिकारी तुरंत ऊपर की मंज़िल पर पहुंच गए। खिड़कियां खोल दी गईं ताकि धुआं बाहर निकल सके। धुआं बहुत ज़्यादा घना था, इसलिए, उसे बाहर निकालने में मदद के लिए ऊपर के आउटलेट खोल दिए गए। फ़ायर ब्रिगेड 5 से 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। दस्तावेज़ पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि चौथी मंज़िल पर, जहां रिकॉर्ड रूम के पास आग लगी थी। आस-पास के किसी भी कमरे में शॉर्ट सर्किट या इसी तरह की किसी बिजली की खराबी के कोई संकेत नहीं दिखे। फिर भी, मीडिया के सवालों के जवाब में, उन्होंने घटनाक्रम की पूरी तरह से जाँच कराने का वादा किया।

केंद्रीय मंत्री पासवान बोले-बाबा श्याम के आशीर्वाद से 100% स्ट्राइक-रेट

बिना मांगे सब कुछ मिलता है यहां, पांचों राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी

सीकर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा- जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में वहां के लोगों ने काफी उत्साह से मतदान किया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार से त्रस्त होकर नरेंद्र मोदी के विचारों की सरकार लाने के लिए वोट किया है। 4 मई को जब परिणाम घोषित होंगे तो इन पांचों राज्यों में एनडीए की नरेंद्र मोदी की विचारधारा की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- लोकसभा चुनाव में खाटूश्यामजी का आशीर्वाद लेकर गया था, तो हंड्रेड पर्सेंट स्ट्राइक रेट रहा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर प्रत्याशी खड़े थे और पांचो प्रत्याशी जीते, आज उसका धन्यवाद जताने के लिए पहुंचा हूं। बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। लोक जनशक्ति पार्टी अगले साल के उत्तरप्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है।

ममता बनर्जी ने हिंसा और अपराध के दम पर राज किया

केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा- पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंसा और अपराध के दम पर राज किया और बर्बादी करने का काम किया। बंगाल की जनता डबल इंजन वाली सरकार बनाकर पश्चिम बंगाल को विकास के राह पर ले जाना चाहती है। 5 राज्यों में कहीं भी कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। बंगाल में भाजपास, तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में **AIDMK** व भाजपा की लड़ाई है।

अब खत्म होती जा रही है कांग्रेस

चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में थोड़ी बहुत बची हुई थी वहां से भी अब खत्म होती जा रही है। जिस तरह कांग्रेस सिमटती जा रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प साकार हो जाएगा। राजस्थान और हरियाणा कांग्रेस के गढ़ थे, अब वहां से भी कांग्रेस साफ होती जा रही है।

राजस्थान में पार्टी का विस्तार किया जाएगा

राजस्थान में भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ने वाली एक बड़ी आबादी है, ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान में भी लोग जनशक्ति पार्टी का विस्तार किया जाएगा। चुनावी दृष्टि से भी पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा।

राजस्थान में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के दौर शुरू हो गए हैं। राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव तक पार्टी को मजबूत कर लिया जाएगा, ताकि प्रत्याशी उतारे जा सकें। खाटूश्यामजी जितनी बार आता हूं उतनी बार यहां सुकून मिलता है। खाटूश्यामजी में अटूट विश्वास है इसलिए पूरे परिवार के साथ आया हूं, क्योंकि यहां बिना मांगे सब कुछ मिलता है।

39 हाईकोर्ट जज एक साथ जयपुर में करेंगे सुनवाई

वकीलों का कार्य बहिष्कार, सीजेआई सूर्यकांत का न्याय-सेतु कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन

जयपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जयपुर पहुचें। सीजेआई का 2 महीने में जयपुर का यह दूसरा दौरा हो रहा हैं। इससे पहले 20 फरवरी को सीजेआई ने साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित तीन दिवसीय कांफ्रेंस का जयपुर में उद्घाटन किया था। सीजेआई शनिवार को जयपुर में रिटायर्ड न्यायाधीशों की भूमिका पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार द बेंच बियॉन्ड रिटायरमेंट को संबोधित करेंगे। इस सेमिनार में सीजेआई के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। सीजेआई की विजिट के चलते शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा सहित 39 जजेज एक साथ जयपुर में बैठेंगे। हाईकोर्ट जयपुर बैंच की स्थापना के बाद संभवत यह पहला मौका है, जब सभी न्यायाधीश एक साथ जयपुर बैंच में बैठकर सुनवाई करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ सभी न्यायाधीश सुनवाई के लिए कोर्ट रूम्स में बैठेंगे, वहीं दूसरी ओर शनिवार वर्किंग के विरोध में हाईकोर्ट में वकील स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।

पहली बार एक साथ 4 लार्जर बैंच

राजस्थान के न्यायिक इतिहास में शनिवार का दिन कई मायनों में खास होने वाला हैं। जानकारों का कहना है कि संभवत ऐसा पहली बार हो रहा है कि हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश एक साथ जयपुर में सुनवाई करेंगे। इसके लिए रोस्टर में बदलाव करते हुए 4 लार्जर बेंच, 6 खंडपीठ और 15 एकलपीठ का गठन किया है। प्रदेश के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक साथ 4 लार्जर (दो से अधिक न्यायधीशों वाली बैंच) बैच गठित हुई हैं।

इस साल के पहले वर्किंग शनिवार से पहले ही हाईकोर्ट बार ने स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पर रहने का फैसला कर लिया था।
इस साल के पहले वर्किंग शनिवार से पहले ही हाईकोर्ट बार ने स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पर रहने का फैसला कर लिया था।

बार-बैंच में गतिरोध बरकरार

हालांकि इन सब के बीच शनिवार-वर्किंग को लेकर बार और बैंच मे चला आ रहा गतिरोध अब भी बरकरार हैं। सीजेआई की जयपुर में मौजूदगी के बाद भी यह गतिरोध नहीं टूट रहा हैं। दरअसल, पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में सीजेआई की उपस्थिति में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक में साल 2026 से प्रत्येक माह के दो शनिवार (पहला-तीसरा) को वर्किंग का फैसला हुआ था।

धुरंधर-2 से फिर शुरू हो गई बाहुबली अतीक अहमद की चर्चाएं

प्रदीप आजाद।

हिंदुस्तान में अपराध की दुनियां में यूं तो कई नाम चर्चित हुए। कई गैंगस्टर्स का खौफ पिछले कुछ वक्त से ऐसा चला आ रहा है कि आज भी लोग और पुलिस उन गैंगस्टर्स के नाम से खौफजदा हैं और गैंगस्टर्स अपने गुर्गों के जरिए आज भी अपने गुनाह का साम्राज्य कायम किए हुए हैं। अब ऐसे गैंगस्टर्स की फेहरिस्त कोई छोटी नहीं, लेकिन आज की केस डायरी में हम जिस नाम का जिक्र कर रहे हैं, ये वो नाम है जिसने सियासत में भी तहलका मचाया और गुनाह के रास्ते पर चलने में भी अपना वर्चस्व कायम किया। आज से करीब तीन साल पहले की एक उस तस्वीर को याद कीजिए, जब खाकी और पब्लिक की मौजूदगी में कुछ बदमाश एक शख्स को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन था...तो चलिए आपको बता देते हैं उस शख्स के बारे में। जिसका नाम आज भी काफी चर्चाओं में है। आपने अतीक अहमद का नाम सुना है। जी हां..वही। जब करीब 3 साल पहले प्रयागराज में ही अतीक अहमद और उसके भाई असरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल वही, अब आप फिल्म धुरंधर 2 भी याद कर लीजिए। क्योंकि इस चर्चित फिल्म में कई किरदारों की खूब चर्चाएं हो रही है और इन्हीं में से एक किरदार है 'आतिफ अहमद' का, जिसे कभी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन, सांसद और विधायक रहे अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है और इनकी हत्या से पहले अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। जबकि उसका भाई असरफ बरेली सेंट्रल जेल में बंद था। अब आपको कहानी कुछ कुछ समझ आ रही होगी। तो चलिए आज बात करते हैं एक वक्त में बाहुबली रहे अतीक अहमद की। दरअसल आज के प्रयागराज और पुराने इलाहाबाद में एक अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर-बसर करते थे। फिरोज का बेटा अतीक अहमद हाईस्कूल में फेल हो गया था। इसके बाद पढ़ाई-लिखाई से उसका मन हट गया और इसकी वजह थी कि उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। इसके लिए अतीक ने शार्ट कट का रास्ता अख्तिया किया। वह रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में 1979 में अतीक के सिर हत्या का पहला आरोप लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। वहीं पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला और उसने चांद बाबा की ही हत्या कर दी। यानि अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा, जब उसने एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। यह उस पर दर्ज हुआ हत्या का पहला केस था और बस, इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने

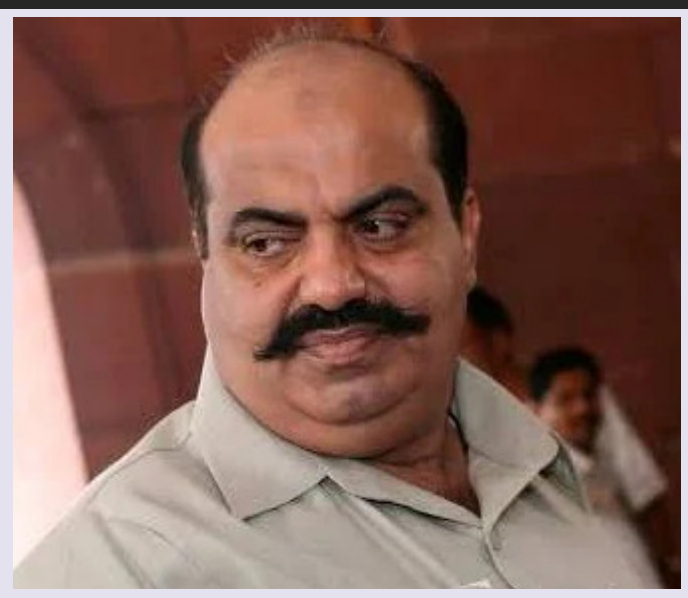

भाई अशरफ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर गैंग तैयार कर ली और फिर शुरू हो गया रंगदारी, हत्या और वसूली का खेल। छोटी उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अतीक ने साल 1980-90 के दशक में खुद को मोस्ट वांटेड माफिया के रूप में स्थापित कर लिया और इस वक्त तक उस पर 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, जमीन हड़पना और आतंकवाद से जुड़े आरोप शामिल थे। लेकिन अतीक की ख्वाहिशें कोई कम नहीं थी और उसने अपने अपराध के काले साये के साथ साथ ही सियासत पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। अतीक अहमद पहली बार 1989 में प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बना। साल 2004 में अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुना गया और केवल यही नहीं बल्कि अतीक पांच बार विधायक भी रहा। इधर सांसद चुने जाने के बाद जिस पश्चिम विधानसभा सीट से वह विधायक था, वो सीट खाली हो गई। जाहिर है इस सीट पर उपचुनाव होना था। इसलिए अतीक ने अपने छोटे भाई असरफ अहमद को मैदान में उतार दिया। इसी बीच बसपा ने कभी अतीक के चेले रहे राजू पाल को टिकट दे दिया। जिसके बाद राजू पाल ने अतीक के भाई असरफ को चुनाव हरा दिया और बस ये हार अतीक पचा नहीं पाया। उसका वर्चस्व ऐसा कि जेल में रहते हुए भी अतीक का साम्राज्य चलता रहा और यहीं से अतीक के वर्चस्व की कहानी शुरू हो गई। जो 44 साल तक हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, धमकी और जमीनों पर कब्जे के बल पर चलती रही। अतीक ने जुर्म का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके पास गुर्गों की एक पूरी फौज थी, जो अतीक के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। जिस पुलिस और सफेदपोशों ने अतीक को बढ़ावा दिया। वही उससे खौफ खाने लगे। प्रयागराज और आसपास के जिलों में अतीक अहमद का खौफ साफ नजर आता था। अतीक की नजर हमेशा जमीनों पर रहती थी। जो जमीन अतीक को पसंद आ गई। मजाल है कब्जेदार उसे हासिल कर पाए या तो वह सीधे-सीधे अतीक को औने-पौने दाम पर जमीन दे दे, नहीं तो इस दुनिया से चल बसे। यही वजह रही कि धीरे-धीरे अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हो गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर 25 जनवरी 2005 को अतीक अहमद के गुर्गों ने प्रयागराज में दिनदहाड़े विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से यूपी में भूचाल आ गया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत कई अन्य गुर्गों को नामजद किया गया और धीरे-धीरे यही मुकदमा अतीक के अंत की वजह बन गया। दरअसल इस मामले के बाद पुलिस ने अतीक अहमद के गुनाहों के पन्ने पलटने शुरू किए। अदालत में मुकदमों की पैरवी तेजी से होने लगी। राजू पाल की हत्या के केस की सुनवाई भी चल रही थी। अब इस केस में मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल खुद वकील था। 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और कुछ गुर्गों ने उमेश पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या उसके घर के पास की गई और इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। अब उमेश पाल की हत्या के बाद एक बार फिर यूपी में तूफान आ गया। लॉ एण्ड आर्डर को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सीएम योगी खुद एक्टिव हुए। धीरे-धीरे कर उमेश पाल की हत्या के आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए जाने लगे। इसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। झांसी में पुलिस ने असद को एनकाउंटर में मार गिराया। अब थोड़ा फ्लेश बैक में चलें तो आपको बता दें कि साल 2009 में सांसद पद से हटने के बाद धीरे-धीरे अतीक अहमद सियासी हाशिए पर चला गया था। कुछ चुनावों में निर्दलीय मैदान में उतरा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वक्त गुजरता गया और साल आया 2017 यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। योगी आदित्यानाथ मुख्यमंत्री बने। जिन्होनें धीरे-धीरे माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब इसमें अतीक अहमद का नंबर भी आया और अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन उसे यूपी की कुछ जेलों में रखा गया लेकिन फिर उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि अतीक अहमद अपने खिलाफ गवाही देने वालों का अपहरण और हत्या और पुलिसकर्मियों को भी धमकाने का काम करता था। अतीक अहमद के खिलाफ 150 से ज्यादा मामले थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अहमद और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की चार्जशीट में अतीक ने खुद कबूल किया था कि उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से सीधे संबंध थे। वो पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियारों की सप्लाई लेता था। जो आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे। पुलिस के अनुसार, अतीक का नेटवर्क नकली नोटों, हथियारों और ड्रग्स के अवैध व्यापार से जुड़ा था, जो पाकिस्तान समर्थित आतंक को बढाने का हिस्सा था। आपको बता दें कि 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद के कथित अपराधों की फेहरिस्त जारी की थी और तब बताया गया था कि उसके ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के क़रीब चार दर्जन मामले दर्ज हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी सलाखों में कैद रहे अतीक़ अहमद का सियासी रसूख़ किसी से छिपा नहीं था। हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे क़रीब सौ से ज्यादा संगीन आरोपों से घिरा अतीक़ अहमद पाँच बार विधायक और एक बार सांसद रह चुका था। कुल मिलाकर अतीक अहमद एक वो शख्स रहा। जिसने सरकार और पुलिस की नाक में दम करने के साथ साथ सियासत में भी अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अब कानून तो अतीक के साथ अपना काम कर रही रहा था। लेकिन इसी बीच करीब तीन साल पहले 15 अप्रेल साल 2023 को जब पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रुटीन चेकअप के लिए जेल से अस्पताल ले जा रही थी तो तीन युवकों ने दोनों भाइयों के ऊपर गोलियां बरसा दी। आखिर गोलियों से छलनी हुए अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो गई। पूरे देश ने दोनों भाइयों की इस मौत को लाइव देखा था और यह हत्या पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी।

जयपाल पूनिया हत्याकांड में पूर्व विधायक का भाई दोषी करार

चार साल पहले हिस्ट्रीशीटर और नमक व्यापारी पर फायरिंग कर किया था मर्डर, आज सुनाई जाएगी सजा

नागौर। चार साल पहले नमक कारोबारी और हिस्ट्रीशीटर जयपाल पूनिया की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक के भाई समेत 9 को दोषी करार दिया है। इस मामले में शनिवार, 25 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल, डीडवाना-कुचामन के नावां में जयपाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बोलेरो में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस मामले को लेकर शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 11 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में तत्कालीन विधायक और कांग्रेस सरकार में उपमुख्य सचेतक रहे महेंद्र सिंह चौधरी के बड़े भाई मोती सिंह को भी दोषी करार दिया गया है।

9 दोषी, 2 को मिला संदेह का लाभ

एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने मामले की सुनवाई करते हुए मोती सिंह सहित 9 आरोपियों रणजीत, मोती सिंह (तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह चौधरी के भाई), फिरोज खान, हारून, संदीप, तेजपाल, राजेश और कृष्ण कुमार को हत्या का दोषी माना है। वहीं, मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों कुलदीप और हनुमान सैनी को पर्याप्त सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।

अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा के अनुसार, न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी सिद्ध कर दिया है, लेकिन सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रखा है। शनिवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी। फैसले के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। घटना के तीन दिन बाद ही 17 मई 2022 को पुलिस ने तत्कालीन विधायक के भाई मोती सिंह सहित 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित की गई एसआईटी और क्राइम ब्रांच ने जांच आगे बढ़ाई और जून 2022 तक अन्य शूटरों और षड्यंत्रकारियों को भी पकड़ लिया गया था। 15 जून 2022 तक की रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में कुल 8 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया था। कुछ आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे, जिन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। बाद में उन्हें अलग-अलग स्थानों से दबोचा गया था। गौरतलब है कि 14 मई 2022 को नावां सिटी के तहसील रोड पर रेलवे फाटक के पास जयपाल पूनिया की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। 4-5 हमलावर बोलेरो गाड़ी से आए थे। बोलेरो से उन्होंने व्यापारी की कार का रास्ता ब्लॉक किया और इसके बाद नीचे उतारकर कार के शीशे तोड़े और व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए थे। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से भाग गए थे। पुलिस घायल व्यापारी को नावां हॉस्पिटल ले गई थी, जहां से डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। रास्ते में व्यापारी ने दम तोड़ दिया था। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में तूल पकड़ा था और तत्कालीन विधायक के भाई मोती सिंह का नाम सामने आने के बाद लंबे समय तक आंदोलन चला था।

सीबीआई जांच की मांग के बीच चले इस कानूनी घटनाक्रम में अब जाकर न्यायालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय आया है। इस मामले में सामने आया था कि मर्डर से पहले मुख्य आरोपी मोती सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर जयपाल पूनिया की रेकी की थी। इसके बाद रणजीत समेत 6 शार्प शूटर्स को लोकेशन देकर फायरिंग के लिए भेज दिया। फायरिंग के बाद शार्प शूटर्स भाग गए थे इसके बाद जब पूनिया को जयपुर रेफर किया गया, तो भी मोती सिंह ने उसका पीछा किया था। वह जानना चाह रहा था कि जयपाल जिंदा है या फिर मर गया।

आईपीएल मैच के लिए टिकट विवादः

एसएमएस स्टेडियम के बाहर छात्रों का हंगामा

प्रमोद कुमार

जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मैचों से पहले टिकट वितरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 25 अप्रैल से शुरू हो रहे मुकाबलों के बीच छात्रों के लिए सस्ती दर पर टिकट देने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में युवा स्टेडियम गेट पर पहुंच गए, लेकिन सीमित टिकट वितरण के बाद अचानक विंडो बंद कर दी गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि टिकटों की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है और उन्हें जानबूझकर वंचित किया जा रहा है। आक्रोशित युवाओं ने स्टेडियम के बाहर जमकर नारेबाजी की और बैरिकेट्स तोड़े व पोस्टर फाड़ दिए। हालात ऐसे बने कि युवाओं ने मुख्य गेट बंद कर वहीं धरना शुरू कर दिया, जिससे आसपास यातायात भी प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया।

गौरतलब है कि 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला प्रस्तावित है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। लेकिन टिकटों को लेकर उठे इस विवाद ने पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे युवाओं को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं, प्रदर्शन कर रही एक छात्रा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कहती नजर आ रही है कि सुबह 6 बजे से लाइन में लगने के बावजूद टिकट नहीं मिली, जबकि ऑनलाइन माध्यम से महंगे दामों पर टिकट खरीदी जा रही हैं। फिलहाल, प्रशासन और आयोजकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए आक्रोशित युवाओं को शांत करना है, ताकि आगामी मैचों के दौरान किसी बड़े व्यवधान की स्थिति न बने।

राजस्थान पर्यटन का वैश्विक भरोसाः सातों महाद्वीपों की भागीदारी के साथ जीआईटीबी के रंग

26-28 अप्रैल तक जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, 50 देशों के टूर ऑपरेटर्स जुटेंगे

जय महल पैलेस में उद्घाटन, जेईसीसी सीतापुरा में होंगे व्यवसायिक सत्र

प्रमोद कुमार

जयपुर। राजस्थान एक बार फिर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। 26 से 28 अप्रैल तक ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार (जीआईटीबी) का 15वां संस्करण जयपुर में आयोजित होगा, जिसमें दुनिया के सातों महाद्वीपों से 50 देशों के विदेशी टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के भरोसेमंद और विविधतापूर्ण गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पर्यटन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बदलते यात्रा रुझानों और अनुभव-आधारित पर्यटन की बढ़ती मांग के बीच प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्घाटन सत्र 26 अप्रैल की शाम जय महल पैलेस में होगा, जबकि 27 और 28 अप्रैल को व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) सत्र जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी), सीतापुरा में आयोजित किए जाएंगे।

यह आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन के अनुसार, दो दिनों में 10,000 से अधिक पूर्व-निर्धारित बी2बी बैठकों के जरिए विदेशी खरीदार सीधे भारतीय प्रदर्शकों, धरोहर और लग्ज़री होटल संचालकों, गंतव्य प्रबंधन कंपनियों, वेलनेस, वन्यजीव, साहसिक और एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) संचालकों से संवाद करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य केवल प्रचार-प्रसार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारियां स्थापित करना है। पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियार ने कहा कि लगातार 15 वर्षों से आयोजित हो रहा जीआईटीबी राजस्थान पर्यटन की विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में विदेशी भागीदारी यह दर्शाती है कि राजस्थान को सुरक्षित, स्थिर और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा रहा है। इस बार जीआईटीबी में एशिया, यूरोप, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशिआनिया सहित सातों महाद्वीपों के देशों की भागीदारी हो रही है, जो इसे विशेष बनाती है। आयोजन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों के लिए जयपुर, सरिस्का, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर और देवगढ़ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के विशेष भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं, ताकि वे राजस्थान की विरासत, संस्कृति और अनुभव-आधारित पर्यटन को नजदीक से समझ सकें। अब राजस्थान केवल किलों और महलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य, जीवंत संस्कृति और विविध अनुभवों के जरिए यह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण गंतव्य बनकर उभर रहा है।

एसएमएस हॉस्पिटल के 38 कार्मिकों की लगाई गणना में ड्यूटी

जयपुर। राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह के आधे मंत्रालयिक कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल में तैनात कुल 65 कर्मचारियों में से 38 अगर जनगणना ड्यूटी पर चले गए तो RGHS, मां योजना, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, मेडिकल और दिव्यांग बोर्ड समेत अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। इसे देखते हुए मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने दखल देते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर इन सभी की ड्यूटी निरस्त करने के सिफारिश की है। दरअसल एसएमएस हॉस्पिटल में वर्तमान में 65 मंत्रालयिक कर्मचारी नियुक्त हैं। इनका डेली रूटिन के काम के लिए आदेश, दिशा-निर्देश निकालना, आवश्यक सेवाओं से संबंधित फाइलों पर काम करना है। करीब 10 दिन पहले 13 अप्रैल को नगर निगम के आदर्श नगर जोन उपायुक्त और जनगणना अधिकारी ने आदेश जारी करके इनमें से 38 कर्मचारियों (करीब 58 फीसदी) की ड्यूटी जनगणना में लगा दी।

आईएएस अफसर आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच पर रोक

जयपुर। डिस्कॉम की चेयरपर्सन और आईएएस आरती डोगरा को 24 घंटे में ही राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के एसीबी जांच के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। आरती डोगरा और डिस्कॉम की ओर से सीनियर एडवोकेट आर एन माथुर ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच में बहस करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन जांच लंबित हैं।

इन सभी जांचों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है।

एकलपीठ ने जताई थी भ्रष्टाचार की आशंका

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया था। जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरके मीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था- डिस्कॉम चेयरपर्सन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर फैसला जानबूझकर कई महीनों तक रोककर रखा था।

बंगाल में मोदी बोले- टीएमसी का दीया बुझने वाला

शाह ने कहा- अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा

कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा। बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को रैली में आरजी कर पीड़िता की मां से मिले। मोदी बोले- जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में मदद की, उसी बेटी को टीएमसी ने उनसे छीन लिया। पीएम मोदी शुक्रवार को रैली में आरजी कर पीड़िता की मां से मिले। मोदी बोले- जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में मदद की, उसी बेटी को टीएमसी ने उनसे छीन लिया।

अभिषेक बनर्जी बोले- अपराधी अब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं

पश्चिम बंगाल के जगतबल्लभपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले चोर, डकैत, हत्यारे और बलात्कारी अपराध करते थे और जेल जाते थे। अब वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आप अपने आसपास देखिए, कोई सभ्य या शालीन व्यक्ति बीजेपी का समर्थन नहीं करता। कोई पढ़ा-लिखा या सम्मानित व्यक्ति बीजेपी के साथ नहीं है। सभी चोर, भ्रष्ट लोग, ठग, शराबी, नशेड़ी, गद्दार और बेईमान लोग बीजेपी में हैं।

पीएम मोदी बोले- महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हमारा लक्ष्य

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। लेकिन कुछ दिन पहले संसद में टीएमसी और उसके सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया। देश चाहता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं चाहती। आज बंगाल में हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर 'मातृ शक्ति भरोसा कार्ड' बांट रहे हैं। हर बहन को हर महीने 3000 रुपए, यानी सालाना 36,000 रुपए की सहायता का आश्वासन दिया जा रहा है।

पीएम ने कहा- टीएमसी ने 15 साल में बंगाल की पहचान खत्म की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 15 साल में टीएमसी सरकार ने बंगाल की पहचान को खत्म कर दिया है। यहां घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। वे बंगाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। एक तरफ टीएमसी का भ्रष्टाचार है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों का अत्याचार। बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा, जब टीएमसी पूरी तरह पराजित होगी और भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता में आएगी। यहां बैठी टीएमसी सरकार वंचित वर्ग के खिलाफ है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बाधा डाल रही है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है, लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है।

पीएम बोले- टीएमसी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं, बीजेपी सरकार में बलात्कारी सुरक्षित नहीं रहेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादवपुर में कहा कि पहले चरण के मतदान से साफ हो गया है कि कई जिलों में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। दूसरे चरण में आपको टीएमसी की पक्की हार और विकसित बंगाल के संकल्प पर मुहर लगानी है। बीजेपी की जीत, चाहे बड़ी हो या निर्णायक, बंगाल में तेज विकास का नया दौर लेकर आएगी। 29 अप्रैल को आपको यह काम करना है। यह बंगाल के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। टीएमसी सरकार में पाले गए अपराधियों और गुंडों, तथा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के दोषियों को कानून सख्त सजा देगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे। टीएमसी शासन में यहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन भाजपा सरकार में कोई भी बलात्कारी या अपराधी सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा, यह मोदी की गारंटी है।

पीएम ने कहा- 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को सिर्फ लूटने का काम किया

पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जाधवपुर में कहा कि बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में बंपर मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद कभी ऐसा नहीं देखा जो इस बार बंगाल के लोगों ने कर दिखाया। हर तरफ यही चर्चा है कि भाजपा को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दूकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी तक, सब भयमुक्त होकर भाजपा की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। हर कोई परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार हैं। पिछले 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का भ्रष्टाचार नहीं इसलिए बंगाल की जनता कह रही है भर्ती घोटाला चोलबे न(भर्ती घोटाला नहीं चलेगा), चीट फंड घोटाला, कोयला खनन घोटाला, गरीबों के राशन की लूट, तस्करों को छूट, कटमनी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा।

पीएम मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की

नाव चलाने वाले को गले लगाया, 1000 दिए; 5 दिन पहले झालमुडी खाई थी

कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुगली नदी में नाव की सवारी की है। इस दौरान पीएम ने खुद से फोटोग्राफी भी की। तस्वीरों में वे हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाविकों से बातचीत भी की। हुगली में नाव की सवारी कराने वाले नाविक को एक हजार रुपए भी दिए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाव की सवारी वाली तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, 'हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है।' इससे पहले पीएम 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झाडग्राम में रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई।

नाविक को दिए 1000 रुपए

पीएम मोदी ने कोलकाता के हुगली घाट पर नाव की सवारी के बाद नाविक गौरांगो बिस्वास को गले लगाया और 1000 रुपए दिए। पीएम ने × पर एक वीडियो शेयर कर लिखा- कल शाम हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था। आज सुबह उसे हुगली नदी से देखा।

7 महीने प्रेग्नेंट नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट बोला- यह महिला की इच्छा का सवाल, उसे डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सात महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन (अबॉर्शन) की इजाजत दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा- यह जन्म लेने वाले बच्चे का सवाल नहीं है। जरूरी यह है कि लड़की क्या चाहती है। अगर वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। भले ही बच्चे को जन्म के बाद गोद देने का ऑप्शन मौजूद हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस स्टेज पर अबॉर्शन करना मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने डिलीवरी के बाद बच्चा गोद देने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लड़की एक नाबालिग लड़के के साथ आपसी सहमति से संबंध के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। नाबालिग की मां ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में तय समयसीमा से आगे जाकर बेटी के अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। लड़की ने भी कहा था कि वह प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती।

वकील ने बताया- प्रेग्नेंसी से तनाव में नाबालिग

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा गया कि इस प्रेग्नेंसी ने नाबालिग को गंभीर मानसिक तनाव दिया है और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग में पहले से ही गंभीर मानसिक तनाव के संकेत दिख रहे हैं। वह आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए गोद दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लड़की और उसके परिवार की पहचान सुरक्षित रहे। उन्होंने नाबालिग को आर्थिक मदद की पेशकश भी की। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने इस तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट महिलाओं को अबॉर्शन के बजाय उनके लिए आर्थिक मदद या गोद लेने जैसे विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

कोर्ट बोला- महिला को प्रजनन संबंधी फैसले लेने की आजादी

कोर्ट ने कहा, 'किसी महिला, खासकर नाबालिग, को इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी पूरा करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना जरूरी है।

बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड 93 प्रतिशत मतदान

2 भाजपा कैंडिडेट पर हमला, पथराव, लाठीचार्ज और बम फेंका गया; तमिलनाडु में पहली बार 85% वोटिंग

कोलकाता/चेन्नई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। दो भाजपा कैंडिडेट पर हमला हुआ। एक को दौडा-दौडाकर पीटा। वहीं, मुर्शिदाबाद के नौदा में बुधवार देर रात देसी बम से हमले में कई लोग घायल हो गए। नादौ में हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों की टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ झडप हुई। वे नौदा के बाद जहां-जहां भी गए, वहां झड़प और हिंसा की घटनाएं हुईं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान 2011 में 78.29% था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। ममता ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ बंपर वोटिंग की है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है। इससे पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को एकसाथ आएंगे।

एसआईआर के बाद वोटिंग बढने का ट्रेंड

बंगाल और तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग की वजह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी मानी जा रही है। इसी साल 9 अप्रैल को केरल, असम, पुडुचेरी और नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ था। केरलम में 78.27% वोटिंग के साथ 39 साल का रिकॉर्ड टूटा था। असम में 85.91%, बिहार में 66.90% और पुडुचेरी 89.87% में इतिहास की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। बंगाल-तमिलनाडु की तरह इन राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर हुई है।

तमिलनाडु में अब तक 14 बार चुनाव, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग

तमिलनाडु के 5.73 करोड वोटर्स ने नया इतिहास रचा।

1967 से अब तक राज्य में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई। इससे पहले सबसे ज्यादा 78.12% वोटिंग 2011 में हुई थी, तब एआईएडीएमके की मुखिया रहीं जयललिता डीएमके को हराकर सत्ता में आई थीं और 10 साल राज्य किया था। एसआईआर में करीब 74 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। 2021 में कुल 6.29 करोड वोटर थे।

तब इन 234 सीटों पर 72.81% मतदान हुआ था, जो 2016 की तुलना में करीब 2% कम था। तब इसे कोविड के असर से जोडा गया था। वैसे राज्य में औसत मतदान प्रतिशत आमतौर पर 70 से 75% के बीच रहता था, लेकिन इस बार यह करीब 12% बडा है।

बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने की 4 वजह

एसआईआर राज्य में 91 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या घट गई है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर वोटिंग करीब 80% और 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 82.17% रही थी। यानी कुल मतदाता घटे, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या लगभग बराबर या ज्यादा रही।

एंटी इनकंबेंसी: राज्य में 15 साल से तृणमूल सरकार है। नेताओं से असंतोष, रोजगार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट जैसे मुद्दे भी ज्यादा मतदान की वजह हो सकते हैं। वहीं, मुस्लिम बहुल जिलों और सीमावर्ती इलाकों में यह एसआईआर और एनआरसी के डर से उपजी प्रतिक्रिया भी मानी जा रही है। इस बार ध्रुवीकरण भी जबरदस्त है। इसलिए माना जा रहा है कि हिंदू मतदाताओं का भी वोट प्रतिशत ज्यादा रहा होगा।

प्रवासी कामगार: यह भी बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से केवल वोट डालने बंगाल लौटे हैं। उन्हें लगा कि इस बार वोट नहीं दिया, तो हमेशा के लिए अधिकार छिन सकता है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा ट्रेन भर कर वोट डालने के लिए लोगों को ला रही है।

आयोग की सख्ती: निर्वाचन आयोग की अभूतपूर्व निगरानी और 2.40 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण मतदाताओं ने बिना किसी डर के मतदान किया।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्यसभा में नोटिस

इस पर 73 सांसदों के दस्तखत, मार्च में दोनों सदनों में खारिज हो चुका प्रस्ताव

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में नोटिस दिया। इस पर 73 सांसदों के दस्तखत हैं। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते।

100 सांसदों के दस्तखत जरूरी

लोकसभा में CEC को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।

कानून के अनुसार प्रस्ताव मंजूर होने पर ही जांच समिति

मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी होती है। जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट 1968 के अनुसार,

अगर दोनों सदनों में एक ही दिन नोटिस दिया जाता है, तो जांच समिति तभी बनेगी जब दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाएंगे।

ट्रम्प के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन

1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी, पार्टी के 10 सांसद विरोध में

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार, किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पडती है।

यहां भी ट्रम्प ने खेल किया। युद्ध 28 फरवरी को छेडा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रम्प के 53 सांसद हैं। जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 हैं। ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं।

ऐसे में अब ट्रम्प 1 मई से पहले किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस कानून में 60 दिन के बाद एक विकल्प और है। राष्ट्रपति एक बार के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए होता है, न कि युद्ध जारी रखने के लिए।

क्या ट्रम्प 60 दिन की सीमा तोड़ सकते हैं

एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रम्प इस समय सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं। अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी यह दलील देते रहे हैं कि संविधान उन्हें सेना के प्रमुख के रूप में कई बड़े अधिकार देता है, इसलिए इस तरह की कानूनी सीमाएं पूरी तरह लागू नहीं होतीं। उदाहरण के तौर पर 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि यह कानून लागू नहीं होता क्योंकि वहां 'लगातार लड़ाई' जैसी स्थिति नहीं थी। ट्रम्प ने भी अपने पहले कार्यकाल में 2019 में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसमें यमन युद्ध में अमेरिका की भूमिका खत्म करने की बात थी। उन्होंने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बताया था। लेकिन अगर इस बार ट्रम्प 60 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं, तो यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किल पैदा कर सकता है। 1. इजराइल-लेबनान सीजफायर बढ़ा: डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में इजराइल और लेबनान के राजदूत स्तर की दूसरी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर को तीन हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया।

नवाचार के नायक: राजस्थान के ये IAS-IPS, अनूठी कार्यशैली से जीता दिल

प्रशासनिक दक्षता के साथ अपनी अनूठी कार्यशैली और नवाचारों के लिए दिए बेहतर उदाहरण, चहुंओर हो रही सराहना

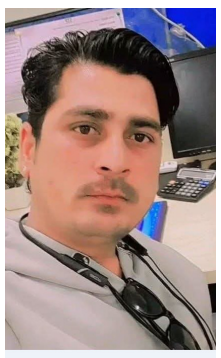

मनोहरसिंह खोखर

जयपुर। प्रदेश में ऐसे कई आईएएस और आईपीएस अफसर है, जो अपने कार्यशैली के साथ अनूठी पहल या अनोखे अंदाज के चलते चर्चा में है। वे केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित न रहकर सामाजिक बदलाव लाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके ये नवाचार ऐसा नहीं है कि तबादला होते ही थम जाते है, बल्कि आगे की तैनाती में भी बरकरार रहते है। खासकर सरहदी जिलों में तैनाती के दौरान कई अफसरों ने प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ अपनी अनूठी कार्यशैली और नवाचारों के लिए सुर्खियां बटोरी। उन्ही में से कुछ चर्चित रहे अफसरों की कार्यशैली के साथ किए नवाचारों पर पेश है खास रिपोर्ट...

आईएएस टीना और रिया, दोनों सगी बहनें, संयोगवश साथ में सम्मानित

जल संचय भागीदारी को लेकर दिल्ली में अच्छा काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की चर्चित आईएएस टीना डाबी ने जहां प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं उदयपुर से इसे रनरअप के तौर उनकी छोटी बहन रिया डाबी ने प्राप्त किया है ।राजस्थान की चर्चित आईएएस टीना डाबी अपनी सक्रियता और नवाचार के लिए काफी चर्चा में रही। हालांकि कुछ राजनेताओं द्वारा उन्हें ट्रोल भी किया गया। नवो बाड़मेर अभियान बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में शहर को स्वच्छ, सुंदर और हाईटेक बनाने के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल रही। इसके बाद टीना डाबी का टोंक तबादला और रिया को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और रसूखदार जिम्मेदारी सौंपी गई है।

IPS चुनाराम अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चित

IPS चूनाराम जाट (2010 बैच) मार्च 2026 में बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक (**SP**) के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से अपनी सक्रिय कार्यशैली और सिंघम छवि के कारण चर्चा में हैं।

उन्होंने नशे के खिलाफ कड़े रुख, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध पर नियंत्रण, और हाल ही में साइकिल पर शहर का दौरा करने जैसी पहल से अपराधियों में खौफ और जनता में विश्वास पैदा किया है। वे इससे पहले भी अन्य जिलों में तैनाती के दौरान अपने अनोखे अंदाज़ (साइकिल गश्त) के लिए काफी चर्चा में रहे।

IAS प्रदीप गवांडे ने शादी के बाद बटोरी सुर्खियां

प्रदीप गवांडे और टीना डाबी की जोडी ने न केवल प्रशासनिक हलकों में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं। इनकी मुलाकात राजस्थान में ड्यूटी के दौरान हुई थी, जहां दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया।

13 साल के उम्र के फासले को दरकिनार करते हुए इस जोडी ने साबित किया कि रिश्तों में परिपक्वता और मानसिक तालमेल सबसे जरूरी होता है। प्रदीप गवांडे राजस्थान कैडर के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं, जो अपनी सादगी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं।

IPS नरेन्द्रसिंह मीणा, तस्करों की तोडी कमर

IPS नरेंद्र सिंह मीणा 2013 बैच के एक भारतीय पुलिस सेवा (**IPS**) अधिकारी हैं, जो विशेष रूप से राजस्थान में अपने कर्तव्यनिष्ठ और सख्त कार्यशैली के लिए चर्चा में रहे हैं। मार्च 2026 में बाड़मेर से हनुमानगढ़ स्थानांतरित होने के

बाद वे सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में विदाई और पदभार ग्रहण को लेकर सुर्खियां बने। हनुमानगढ़ आने से पहले वे लगभग दो वर्षों (फरवरी 2024 से मार्च 2026) तक बाड़मेर के एसपी रहे, जहाँ उन्होंने ड्रग माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन सीमा और अन्य अभियानों के तहत बड़ी कार्रवाइयां कीं, जिसमें कई स्वष्ठ (मेफेड्रोन) फैक्ट्री पकड़ी गई थीं। कार्यवाईयों से मानो तस्करो की कमर ही तोड दी थी।

IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी, अनूठी पहल नो ड्यूटी ऑन बर्थडे पर चर्चा में

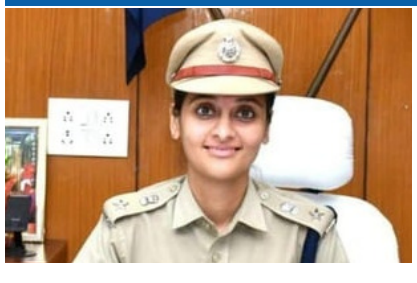

IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी ने सवाईमाधोपुर में **SP** रहते हुए अपनी अनूठी पहल नो ड्यूटी ऑन बर्थडे के कारण चर्चा में हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनके, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के जन्मदिन पर छुट्टी (**Mandatory Leave**) देने का आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य पुलिसबल का मनोबल बढ़ाना है। 2018 बैच की **IPS** ज्येष्ठा मैत्रेयी ने पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार, अपराधियों की गिरफ्तारी और गश्त व्यवस्था को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने थानों का निरीक्षण करने के साथ होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जो पुलिसिंग के साथ अन्य विभागों का सहयोगी कहा जाता है।

IPS पी डी नित्या, कड़े तेवर के साथ सादगी की मिसाल

जोधपुर ग्रामीण की एसपी पी डी नित्या (**IPS**) अपने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही अपनी सादगी, कड़े तेवर और अनूठे कार्यशैली के कारण चर्चा में हैं। मार्च 2026 में कार्यभार संभालते ही उन्होंने नशे की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का ऐलान किया है।

ओसियां थाने के निरीक्षण के दौरान उनके स्वागत में बिछाए गए लाल कारपेट (**Red Carpet**) को नजरअंदाज कर साइड से चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसे सादगी के रूप में सराहा गया।

राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा, पार्टी में बड़ी फूट

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा में शामिल होंगे। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और जालंधर में उनके घर 10 दिन पहले (15 अप्रैल) ईडी ने छापेमारी की थी। राघव ने बताया कि पार्टी के दो-तिहाई सांसदों ने यह फैसला लिया। इसलिए दलबदल कानून लगने का कोई मतलब नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा पिछले कुछ सालों से, मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। हमने यह फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। राघव चड्ढा ने कहा- राज्यसभा में आप के 10 सांसद हैं, जिनमें से दो-तिहाई, यानी 7 हमारे साथ हैं। इनमें राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, राजेंदर गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 सीटें जीती थीं।

राघव ने 2 साल पहले दिए थे अलगाव के संकेत

21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तब राघव ने न कुछ बोला, न कुछ लिखा। फरवरी 2025 में जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, तो आप को करारी हार मिली। सिर्फ 22 सीटें

जीतीं। जबकि BJP ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तब राघव चुप्पी साधे रहे। पार्टी के किसी कार्यक्रम में भी नहीं दिखे। 2025 की शुरुआत में ही राघव के सोशल मीडिया से आप का बैनर और चुनाव निशान हटने लगे। आप के अंदर चर्चा होने लगी कि राघव पार्टी के बजाय पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं। न पार्टी दफ्तर आते हैं, न किसी नेता से मिलते हैं। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित बाकी आरोपियों को शराब नीति घोटाले में CBI के मामले से बरी कर दिया। आप ने इस का जश्न मनाया, लेकिन राघव नदारद रहे। ईरान जंग छिड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पार्टीलाइन पर संसद में बोलने से इनकार कर दिया था। हाल ही में जब पार्टी व्हिव के तहत आप सांसदों ने वॉकआउट किया, तब राघव सदन में मौजूद रहे।

मान बोले- हिम्मत है तो मेरे घर छापा मारो

भगवंत मान बोले- आम आदमी पार्टी इंकलाबी सोच का नाम है। यहां कोई पैसा बनाने नहीं आता। सब अपना कॅरियर छोड़कर आए हैं। मैं कहता हूं ईडी से आओ भगवंत के घर छापा मारो। केजरीवाल-सिसोदिया को जेल में रखा, क्या मिल गया। आप में हिम्मत है तो आओ। मेरे साथ पंजाब के लोग हैं, उनके प्यार की कोई कीमत नहीं है।

भगवंत मान बोले- ये वही वॉशिंग मशीन, जिससे पवार की पार्टी तोडी

पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- इन लोगों ने आज हमारी पार्टी के सांसदों को तोडा। ये वही वॉशिंग मशीन है, जो शरद पवार की पार्टी तोडने में इस्तेमाल की गई थी। पंजाबी जब प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, जब उनसे धोखा किया जाता है तो पंजाबी जो करते हैं उन्हें कई पीडियां याद रखती हैं।

कांग्रेस सांसद बोले- मेन आर्किटेक्ट ने ही साथ छोड़ दिया

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जब पार्टी के मेन आर्किटेक्ट ने ही साथ छोड़ दिया, तो यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। जो नेता पहले दूसरों पर सवाल उठाते थे, अब उन्हें खुद अपने हालात पर सफाई देनी पड़ेगी। आने वाले चुनावों से पहले पार्टी के बाकी सांसद भी साथ छोड़ सकते हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रिक, प्रकाशन, संपादक - नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रिक एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झेलना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) प्रकाशित प्रबंध संपादक - पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)